

[2023] 2 एस. सी. आर 1

ए.

केंद्रीय आयोग के आयुक्त, इलाहाबाद बनाम.

मेसर्स जे. आर. ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। (2009 की सिविल अपील सं. 8502) मार्च 1, 2023

बी.

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1994 -न्यायालयआन्यायालयरन्यायालय.न्यायालय
न्यायालय 6 न्यायालय न्यायालय(न्यायालयपन्यायालयीन्यायालय)न्यायालय
न्यायालय(न्यायालय i न्यायालय i न्यायालय)न्यायालय-
न्यायालयसन्यायालयन्यायालयपन्यायालयिन्यायालयरन्यायालयिन्यायालयटन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालय न्यायालयमन्यायालयून्यायालयलन्यायालयन्यायालययन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयिन्यायालयरन्यायालयन्यायालयधन्यायालयान्यायालयरन्यायालयिन्यायालय
तन्यायालय न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयनन्यायालयान्यायालय-प्रत्यर्थी न्यायालय
न्यायालयजन्यायालयैन्यायालयवन्यायालयिन्यायालयकन्यायालय
न्यायालयरन्यायालयसन्यायालयान्यायालययन्यायालयनन्यायालयोन्यायालयन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयिन्यायालयरन्यायालयन्यायालयमन्यायालयान्यायालयणन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयन्यायालय न्यायालयलन्यायालयगन्यायालयान्यायालय
न्यायालयहन्यायालयुन्यायालयआन्यायालय न्यायालयथन्यायालयान्यायालय
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय न्यायालयकन्यायालयिन्यायालयसन्यायालय
न्यायालयउन्यायालयदन्यायालयन्यायालयदन्यायालयेन्यायालयशन्यायालयन्यायालययन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयपन्यायालयन्यायालयतन्यायालयान्यायालयनन्यायालयगन्यायालयन्यायालय
जन्यायालय न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयपन्यायालयनन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयइन्यायालयकन्यायालयान्यायालयईन्यायालय न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयिन्यायालयशन्यायालयेन्यायालयषन्यायालय
न्यायालयरन्यायालयून्यायालयपन्यायालय न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयून्यायालयतन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयन्यायालयपन्यायालयिन्यायालयरन्यायालयिन्यायालयटन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय न्यायालयखन्यायालयरन्यायालयीन्यायालयदन्यायालय

[illegible]

[illegible]

सी.

डी.

ई.

ए. के. रॉय बनाम वोल्टास लिमिटेड (1973) 3 एससीसी 503:[1973] 2 एससीआर 1089-पर निर्भर था।

एफ.

भारत संघ बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स (1963)

1 पूरक।एस. सी. सी. 586-संदर्भित।

वैक्यूम ऑयल कंपनी बनाम भारत के लिए राज्य सचिव

1932 पी. सी. 168-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

जी.

[1973] 2 एससीआर 1089

पर भरोसा किया गया |

पैरा 7 (1963) 1 पूरक।एस. सी. सी. 586 पैरा 8 ए को संदर्भित करता है।

एच.

1

2

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2009 की सिविल अपील सं. 8502।

2001 की उत्पाद शुल्क अपील संख्या 467 में सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से।

बी.

एन. वेंकटरमण, ए. एस. जी., मुकेश कुमार मरोरिया, रुपेश कुमार, अदित खुराना, वंशजा शुक्ला, सुश्री प्रीति रानी, संतोष कुमार, धर्म दत्ता वर्मा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

वी. लक्ष्मीकुमारन, सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन, सुश्री अपेक्षा मेहता, सुश्री फाल्गुनी गुप्ता, सुश्री नेहा चौधरी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भट्ट, न्याय०

1. राजस्व ने यह अपील सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.), प्रधान पीठ, नई दिल्ली दिनांक 27.07.2009 के आदेश से व्यथित होकर दायर की है। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने सी. ए. संख्या 4975/2002 में इस न्यायालय द्वारा रिमांड आदेश पर अपना आदेश दिनांक 12.11.2007 दिया था।

डी.

2. प्रत्यर्थी-निर्धारिती जैविक रसायनों का निर्माण करता है जिसके उद्देश्यों के लिए वह उत्तर प्रदेश के कप्तानगंज में अपनी इकाई से विशेष रूप से विकृत आत्माओं (इसके बाद 'एस. डी. एस.') का उत्पादन करता है। एस. डी. एस. के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल में से एक गुड़ है। निर्धारिती को निम्नलिखित अवधि के लिए तीन कारणदर्शक नोटिस जारी किए गए थे:-
ए.

ई.

एफ.

जी.

एच.

3

केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, इलाहाबाद बनाम एम/एस जे. आर. ऑर्गेनिक्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

3. प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने तर्क दिया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1994 के नियम 6 (पी) (ii) के संदर्भ में उचित मूल्यांकन पर, एस. डी. एस. का मूल्य कप्तानगंज में इसके आंतरिक

उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, मूल रूप से आदेश अन्यथा था, जो कारण बताए जाने के नोटिस में की गई मांग की पुष्टि करता है। चूंकि पहले कारण दर्शाओ नोटिस में एक विस्तारित अवधि शामिल थी, इसलिए जुर्माना भी लगाया गया था। इससे व्यथित होकर, निर्धारिती ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. से संपर्क किया, जिसने अपने दिनांक 20.02.2002 के आदेश द्वारा अपील की अनुमति देते हुए कहा कि आयुक्त द्वारा अपनाई गई विधि गलत थी। आयुक्त ने एस. डी. एस. के मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, एक विशिष्ट तिथि पर सराय जिले, गोरखपुर में एक अन्य इकाई में प्रचलित एस. डी. एस. के उत्पाद की उच्चतम दर निर्धारित की थी। 4. राजस्व की अपील को इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसने मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया, यह देखते हुए कि केवल उच्चतम दर की अस्वीकृति अपर्याप्त थी और न्यायालय को निर्धारण अधिकारी के न्यायिक विवेक के आधार पर निर्णय लेना था कि क्या निर्धारण में कोई तर्क था और मूल्यांकन का उचित तरीका क्या था।

बी.

सी.

डी.

5. रिमांड आयोजित होने के बाद दूसरे दौर में सी. ई. एस. टी. ए. टी., अन्य बातों के साथ-साथ, अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद इस प्रकार है:

“सामान की सामान्य कीमत वह कीमत है जिस पर सामान को थोक व्यापार के दौरान 'सामान्य रूप से' बेचा जाता है, यह थोक व्यापार के पाठ्यक्रम का एक प्रकार का प्रतिनिधि मूल्य है। यह एक विशेष अवधि के दौरान माल का एक प्रकार का प्रतिनिधि मूल्य है। ए. के. रॉय और एक अन्य बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। वोल्टास लिमिटेड (ऊपर), पैरा '19' में निर्णय में कहा गया है कि उस कीमत का निर्धारण करते समय जो कर लगाए जाने वाले माल के वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, कीमत हर मामले में रुढ़िवादी होनी चाहिए। इसलिए, नियम 6 (बी) (आई) को लागू करके कैप्टिव खपत के लिए मंजूरी दी जा रही वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करते समय, उसी निर्धारिती या अन्य कर निर्धारकों की तुलनीय वस्तुओं की कीमत के आधार पर, सबसे रुढ़िवादी कीमत को अपनाया जाना चाहिए, न कि कीमतों के उच्चतम, क्योंकि यह सामान्य कीमत के चरित्र को खो देगा।”

ई.

एफ.

जी.

6. राजस्व के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने आयुक्त के इस दृढ़ संकल्प को स्वीकार नहीं किया कि माल का मूल्य नियम 6 (बी) (आई) के तहत ठीक से

निर्धारित किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उस प्रावधान में उल्लिखित विभिन्न घटकों को देखते हुए,

एच.

4

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

राजस्व भौतिक विशेषताओं और माल के निकटतम पता लगाने योग्य मूल्य जैसे कारकों के आधार पर मूल्य तय करने के लिए बाध्य था। इन परिस्थितियों को देखते हुए, गोरखपुर की सराय डिस्टिलरी में किसी विशेष दिन (जब यह अपनी उच्चतम कीमत पर थी) माल के मूल्य पर खुद को आधारित करने के लिए आयुक्त द्वारा प्रयोग किया गया विवेकाधिकार वैध और कानूनी था।

बी.

7. पक्षकारों के अभिलेखों और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि विवादित आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इस न्यायालय ने अपने फैसले में ए. के. रॉय बनाम के रूप में रिपोर्ट किया। वोल्टास लिमिटेड 1 'निम्नलिखित रूप में आयोजित:-

“21. अगला सवाल है: 'थोक नकद मूल्य' शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है? वैक्यूम ऑयल कंपनी बनाम काउंसिल में भारत के राज्य सचिव में, यह माना गया था कि इस शब्द का अर्थ खुदरा व्यापारियों द्वारा थोक खरीद पर भुगतान की गई कीमत है। विचार का सार यह है कि खरीद थोक खरीद होनी चाहिए न कि खुदरा। दूसरे शब्दों में, बिक्री थोक होनी चाहिए न कि खुदरा ताकि प्राप्त मूल्य को 'थोक नकद मूल्य' कहा जा सके। उस मामले में प्रिवी काउंसिल के समक्ष अपीलार्थियों ने बॉम्बे में एक विशेष उत्पादन और निशान के स्नेहक तेल की बहुत बड़ी मात्रा का आयात किया। उन्होंने इसे सीधे कई ग्राहकों को बेच दिया, कभी भी डीलरों को नहीं। चाहे बड़ी या छोटी मात्रा में खरीदा गया हो, उनके द्वारा ली गई कीमत समान थी, सिवाय इसके कि यदि कोई उपभोक्ता उनसे एक वर्ष के लिए अपनी सभी आवश्यकताओं को खरीदने का अनुबंध करता है, तो वह वर्ष में खरीदी गई मात्रा के अनुसार 2-1/2 से 15 प्रतिशत तक की छूट का हकदार था। बम्बई में इसी तरह का और गुणवत्ता का कोई अन्य स्नेहक तेल नहीं बेचा गया था। इस सवाल पर कि क्या अपीलार्थी समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 30 के खंड (ए) या खंड (बी) के आधार पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य था, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि चूंकि बिक्री ग्राहकों को प्रत्यक्ष थी, इसलिए माल का वास्तविक मूल्य धारा 30 के खंड (ए) के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है और धारा 30 का वह खंड (बी) लागू था। उनके लॉर्डशिप्स ने कहा कि उस कीमत को निर्धारित करने में जो 'कर' लगाए जाने वाले माल के वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, कीमत हर मामले में रूढ़िवादी

होनी चाहिए और विशेष रूप से माल के संबंध में किए गए किसी भी आयात के बाद के शुल्क के लिए किसी भी लोडिंग से मुक्त होनी चाहिए। “कीमत एक कीमत होनी चाहिए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1 1973 (3) एससीसी 503 ए

5

केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, इलाहाबाद बनाम एम./एस. जे. आर. ऑर्गेनिक्स लिमिटेड।

वस्तुओं के लिए। क्योंकि वे दोनों आयात के 'समय' और 'स्थान' पर हैं। यह एक 'नकद मूल्य' होना चाहिए, जिसका अर्थ है किसी खरीदार को ऋण या अन्य लाभ के लिए किसी भी वृद्धि से मुक्त मूल्य; यह एक शुद्ध मूल्य होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह एक मूल्य 'कम व्यापार छूट' है। इसलिए उनके प्रभुत्वों का मानना था कि 'थोक मूल्य' शब्दों का उपयोग खंड में 'खुदरा मूल्य' के विपरीत किया गया था, और यह कि न केवल इस तरह के शब्दों का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अर्थ है, बल्कि क्योंकि 'व्यापार छूट' शब्दों के साथ उनका जुड़ाव इंगित करता है कि व्यापार के लिए बिक्री वे हैं जो विचार में हैं, और यह भी कि केवल इस शब्द के साथ उस अर्थ को जोड़ने से आयात के बाद के खर्चों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोडिंग से मुक्त 'थोक मूल्य' है, जिसे व्यवसाय के मामले में हमेशा उपभोक्ता से लिया जाना चाहिए, और जिन्हें समाप्त कर दिया जाता है।”

बी.

सी.

8. जैसा कि वोल्टास लिमिटेड (ऊपर) में स्पष्ट है कि उसने पिछले अधिकारियों का हवाला दिया था।

जैसे 'वैक्यूम ऑयल कंपनी बनाम भारत के लिए राज्य सचिव 2' और 'भारत संघ बनाम दिल्ली क्वॉथ एंड जनरल मिल्स 3'।

डी.

9. इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित स्पष्ट सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करते समय सबसे रूढ़िवादी मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इस न्यायालय की राय में सी. ई. एस. टी. ए. टी. दृष्टिकोण और निष्कर्षों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। सी. ई. एस. टी. ए. टी. के विवादित आदेश की तदनुसार पुष्टि की जाती है।

ई.

10. इसलिए याचिका खारिज की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

एफ.

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायक: महेंद्र यादव, एलसीआरए)

जी.

2 एयर 1932 पी. सी. 168

3 1963 पूरक।(1) एस. सी. सी. 586

एच.